(d) It is proposed to introduce it progressively after successful field trial.

Laying of New Track in South Central Railways

2181. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some new track laying work in South Central Railways is pending for over 10 years after commencement;

(b) the details of all track laying proposals where is under way presently;

(c) the approximate date of completion of each such work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALIKARJUN): (a) There is only one such work of Track Renewal. It is being done with Second hand materials in Trimulgherry Military Siding. Renewal in 4.78 km. length out of 11.33 km. has been completed and the balance work is in progress. The work has been delayed for want of adequate funds not having been deposited by Military authorities towards their share of cost.

(b) There are 56 old works and 26 New Works of 1995-96 where work is under way presently, the details of which are given below:

Year	No. of works
1979-80	1
1989-90	2
1990-91	2
1991-92	3
1992-93	6
1993-94	18
1994-95	24
1995-96	26
	82

(c) 25 works out of the above are planned to be completed in 1995-96 and balance are proposed to be completed progressively by 1998-99, subject to availability of funds and materials.

बिहार को एल॰ पी॰ जी॰/पेट्रोल/डीजल की एजेन्सियों का आबंटन

2182. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में आबंटित की गई एल॰पी॰जी॰ और पेट्रोल/डीजल की एजेन्सियों के नाम और पते क्या-क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्री के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत आबंटित की गई एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत एजेन्सियों का आवंटन करते समय किन-किन बातों पर विचार किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) मार्च, 1995 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 135 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 40 एल॰ पी॰ जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया था। इनमें से 3 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों और 10 एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन अनुकंपा आधार पर विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत किया गया।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और 1.4.1995 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों को अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विवेकाधीन आबंटन करने के लिए सरकार हेतु मार्गदर्शी घटक निम्नानुसार होंगे;

(i) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परन्तु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(ii) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कर्मी/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के समय स्थायीरूप से अपंग हो गए हों।

(v) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात विधवा, अभिभावक, संतान।

(vi) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(vii) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक है और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(viii) विवेकाधीन आबंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन सामान्य रूप से 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।

किसी उम्मीदवार को विवेकाधीन आबंटन निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन किया जाएगा:

(1) भारत का नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(i) पति/पत्नी

(ii) पिता/माता

(iii) भाई

(iv) पुत्र/पुत्रवधु

Installation of Speed Governors in Redline Buses

2183. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there has been no respite from the killings on the roads by the redlines nor there has been any progress in making these killings as murders to bring them within the scope of section 302 of I.P.C.

(b) if so, the reasons therefor and the steps Government have taken or propose to take to discipline the redlines;

(c) the number of persons killed on the roads by redlines in the last 12 months, month-wise;

(d) whether the Delhi High Court had directed the installation of speed governors in the redline buses but the same have not yet been installed therein even after a lapse of more than one year; and

(e) if so, the reasons therefor and the steps taken in that direction by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes Sir. The offence of causing death by rash and negligent driving is punishable under section 304-A/IPC. Such offences do not come under the scope of section of 302-IPC.

(b) The steps being taken by Delhi Police and Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi to discipline redline buses are given in Statement-I (*See* below)

(c) The number of persons killed by redline buses during last 12 months is given in Statement-II (*See* below).

(d) and (e) Yes Sir. As per information received from Government of Delhi, installation of speed governors has been made mandatory under the permit conditions of Redline buses decided by STA. 305 buses have been prosecuted by the Enforcement Staff of the Transport Department for tampering with the speed governors.

Statement I

**Steps being taken by Government of Delhi to discipline Redline Buses*

1. Refresher courses/proficiency training for all drivers of public services vehicles including redline drivers is being imparted at Government Motor Vehicle Training School.